

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 01 अक्टूबर, 2022

विषय- जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्लू०ई०) के अंतर्गत आर०पी० के किमी००४५.०० से चरकडा,माची, देवहार,दरेव, मडपा संपर्क मार्ग किमी० ००.०० से २२.०० तक के निर्माण हेतु कुल १५.२५५ हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी एवं बाधक १७० वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव सं०-एफपी/यूपी/रोड/३४१६०/२०१८)

महोदय,

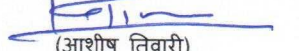
उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-८५१/११-सी- एफपी/यूपी/ रोड/३४१६०/२०१८ दिनांक ०९.०९-२०२१ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सोनभद्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्लू०ई०) के अंतर्गत आर०पी० के किमी००४५.०० से चरकडा,माची, देवहार,दरेव, मडपा संपर्क मार्ग किमी० ००.०० से २२.०० तक के निर्माण हेतु कुल १५.२५५ हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी एवं बाधक १७० वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में शासन के पत्र दिनांक २८-८-२०२० द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति का बिन्दुवार अनुपालन आख्या के आधार पर कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों एवं मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों को सम्मिलित करते हुए एतद्वारा विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाती है:-

1. The forest area involved is not within a National Park and/or a Wild Life Sanctuary.
2. User Agency (UA) shall explore all feasible alternatives to minimize use of forest land.
3. Forest land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable.
4. The UA will submit scheme for Compensatory Afforestation as per extant guidelines in the matter.
5. The UA shall pay the applicable NPV in pursuance of the orders of the Hon'ble Supreme Court.
6. In addition to monthly report of diversions of forest land under General Approval accorded by MoEF&CC, each State/UT Government shall submit half yearly reports for the period ending June 30 and December 31 containing details of all forest lands diverted under the General Approval along with the actual status of actual utilization of the forest lands so diverted for the stated purpose, to the MoEF&CC and its concerned Regional Office.
7. The diversions and compliance to the conditions will be monitored by the concerned Regional Office, MoEF&CC.
8. The legal status of the land shall remain unchanged.
9. The project site should be outside Protected Area Network and eco-sensitive zones (ESZ).
10. The user agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator for Forests and from State/UT Government
11. The Nodal Officer (Forest Conservator) shall submit monthly report to the concerned Regional office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases.
12. The User Agency shall be responsible for ant loss to flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures in this regard.
13. The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal
14. Entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA, 2006 shall be completed before grant of approval for diversion of such forest land.
15. The State/UT Forest Department or State/UT Government or the concerned Regional Office, may impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and/or development of forests
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना में अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वृक्षों का पातन वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा तथा पातन लागिंग आदि का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वनों की क्षति न हो।
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास के मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

19. प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण और 10 वर्षों के लिये रख-रखाव किया जायेगा।
20. मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995-गौडावर्मन थिरूमल्कपाद बनाम भारत संघ व अन्य के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा किये जाने की व्यवस्था में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश पत्रा0 सं0 5-3/2011-एफसी(vol-1) दिनांक 06-01-2022 द्वारा पुर्ननिर्धारण कर दिया गया है। उक्त आदेश का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
21. उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।
23. भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।
24. समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
25. उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
26. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
27. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वर्णित प्रकरण से संबंधित उपरोक्त शर्तें/प्रतिबंधों(Terms & Conditions) के अनुपालन के संबंध में अपनी सत्यापन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी
28. परियोजना में बाधक 170वृक्ष हैं। अतएव निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 16-8-2021 के अंतर्गत ई0टी0टी0 का अनुपालन किया जायेगा।
29. प्रश्नगत अनुमति आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
30. प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फैलिंग, लागिंग एवं

ट्रान्सपोर्टेशन चार्ज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- (1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार, लखनऊ।
- (2)- मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर।
- (3)- जिलाधिकारी सोनभद्र।
- (4) प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र ।
- (5)- अधिशासी अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र
- (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव